नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 159
दि. 08.10.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

'आपके स्वागत के लिए उत्सुक हूं...', पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात, जन्मदिन की दी बधाई

नई दिल्ली, (जीएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और उन्हें 73वें जन्मदिन की बधाई दी. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-रूस के विशेष और प्रिविलेजड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके स्वास्थ्य और सभी प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक सहयोग को और ऊंचाई पर ले जाने का अवसर तलाश रहा है.

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. यह मुलाकात भारत में आयोजित होने वाले 23वें इंडिया-रूस एनुअल समिट में होगी. ये समिट इसी साल दिसंबर में होना है.

इस समिट के माध्यम से दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की योजना बना रहे हैं. पीएम मोदी ने जुलाई 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन को भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था.

रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में भारत के दौरे पर आए थे. उन्होंने 21वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था.

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडा की प्रगति की समीक्षा भी की. इसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की दिशा पर चर्चा हुई. भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष और प्रिविलेजड रणनीतिक साझेदारी रही है, और दोनों देश इसे और गहरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं.

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यह फोन संवाद इस बात का संकेत है कि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को न केवल बरकरार रखना चाहते हैं, बल्कि उसे और विकसित करने के लिए नए मार्ग खोज रहे हैं. इससे आगामी इंडिया-रूस एनुअल समिट में सहयोग के नए क्षेत्र और संयुक्त पहलाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है.

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सतत और समग्र दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. दोनों नेताओं की यह बातचीत वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

युद्ध का मैदान बदल गया है, भविष्य के युद्ध एल्गोरिदम, ऑटोनॉमस सिस्टम और एआई से लड़े जाएंगे; ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और निर्देशित-ऊर्जा हथियार भविष्य को परिभाषित करेंगे: रक्षा मंत्री

रक्षा पूंजी अधिग्रहण वित्त वर्ष 2021-22 में 74,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, यह केवल सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि निर्भरता से आत्मविश्वास की मानसिकता में बदलाव है

आईडेक्स नवप्रवर्तकों से भारत का पहला रक्षा यूनिकॉर्न बनाने की अपील, युवाओं से भारत के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह

आप एक ऐसे नए भारत के निमार्ता हैं जो अपने लिए डिजाइन, विकास और उत्पादन में विश्वास रखता है, आपके द्वारा लाई गई ऊर्जा और नवोन्मेषण प्रौद्योगिकीय रूप से आत्मनिर्भर भारत की कुंजी हैं: रक्षा मंत्री

आज 650 से अधिक आईडेक्स विजेता उभरे हैं और 3,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रोटोटाइप की खरीद सुनिश्चित की गई है, यह भारत के रक्षा नवोन्मेषण परिदृश्य में एक क्रांति का प्रतीक है

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 7 अक्टूबर, 2025 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन से पहले 'रक्षा नवाचार संवादः आईडेक्स स्टार्टअप्स के साथ परस्पर संवाद' के दौरान कहा "युद्ध का मैदान बदल गया है। भविष्य के युद्ध एल्गोरिदम, ऑटोनॉमस सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़े जाएंगे। ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम, क्वांटम कंप्यूटिंग और निर्देशित-ऊर्जा हथियार भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन देखा है,"। उन्होंने नवप्रवर्तकों से विद्यमान समाधानों से आगे सोचने और युद्ध को नई परिभाषा देने वाली प्रोद्योगिकियों का विकास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें प्रौद्योगिकी में न तो नकलची बनना है और न ही अनुयायी, बल्कि हमें विश्व के लिए सृजक और मानक-निर्धारक बनना है।"

स्वदेशीकरण में उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू स्रोतों से रक्षा पूंजी अधिग्रहण 2021-22 में 74,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने इस बदलाव को "केवल एक सांख्यिकीय परिवर्तन नहीं, बल्कि निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर मानसिकता में बदलाव" बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत, वार्षिक खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए आरक्षित है और 350 से अधिक वस्तुएं विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित की गई हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, "रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता एक नारे से आगे बढ़कर एक आंदोलन बन गई है। नीति से व्यवहार तक और नवाचार से प्रभाव तक, यह परिवर्तन हमारे नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा संभव बनाया गया है।"

श्री राजनाथ सिंह ने स्टार्टअप्स को ऊंचे मानक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत में आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, लेकिन रक्षा क्षेत्र में एक भी नहीं है। उन्होंने स्टार्टअप्स से इस स्थिति को बदलने का आ'ान किया। उन्होंने कहा, "भारत का पहला रक्षा यूनिकॉर्न आपके बीच से निकलना चाहिए। यह न केवल आपके लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी।" उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को दोहराया कि सरकार नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और विचार से लेकर कार्यान्वयन तक हर कदम पर उनके साथ रहेगी।

रक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन और 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात में रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धियों में योगदान देने वाले नवप्रवर्तकों के सामूहिक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा, "आप एक ऐसे नए भारत के निमार्ता हैं जो अपने लिए डिजाइन, विकास और उत्पादन में विश्वास रखता है। आपके द्वारा लाई गई ऊर्जा और नवाचार, प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकीय रूप से आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

2018 में आईडेक्स की शुरूआत का स्मरण करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने इसे एक रूपांतरकारी पहल बताया जिसने भारत में रक्षा नवाचार का लोकतंत्रीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जब आईडेक्स की शुरूआत हुई थी, तो इसका विचार सरल लेकिन शक्तिशाली था, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं की प्रतिभा को सशस्त्र बलों की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं से जोड़ना था। उन्होंने कहा, "आज केवल सात वर्षों में, 650 से अधिक आईडेक्स विजेता उभरे हैं और 3,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रोटोटाइप की खरीद सुनिश्चित की गई है। यह भारत के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक क्रांति का प्रतीक है।"

रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि आईडेक्स से पहले, भारतीय प्रतिभाएं, विशेष रूप से आईटी, दूरसंचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दे रही थीं, लेकिन रक्षा क्षेत्र में उनका कम उपयोग हो रहा था। उन्होंने कहा, "आईडेक्स के माध्यम से, हमने यह सुनिश्चित किया कि भारत की प्रतिभाएं भारत की सुरक्षा के लिए काम करें। आज, यह पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो भारतीय रक्षा विनिर्माण के भविष्य को आकार दे रहा है।"

श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने रक्षा खरीद, उत्पादन और परीक्षण अवसंरचना में सुधारों के माध्यम से स्टार्टअप्स और एमएसएमई की सहायता करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए, नई रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम-2025) पांच वर्षों के लिए सुनिश्चित ऑर्डर प्रदान करती है, जिसे पांच वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है, जिससे नवप्रवर्तकों को बहुप्रतीक्षित स्थिरता और पूर्वानुमानशीलता मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने, परीक्षणों में तेजी लाने और नवीन समाधानों के लिए सुनिश्चित खरीद सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) में सुधार जारी हैं।

रक्षा नवाचार इको-सिस्टम को मजबूत करने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने रेखांकित किया "आईडीईएक्स, प्रौद्योगिकी विकास निधि, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना और स्व-प्रमाणन प्रावधानों के माध्यम से, हम एक व्यापक ढांचा विकसित कर रहे हैं जहां नवाचार को प्रोत्साहित, समर्थित और बढ़ाया जाता है। हमारा उद्देश्य भारत को न केवल एक रक्षा विनिमार्ता, बल्कि विश्व के लिए एक रक्षा नवप्रवर्तक बनाना है।"

ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किए गए रेफी एम. फाइबर और ग्रेविटी सिस्टम्स जैसे आईडेक्स विजेताओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवाचार अब वैश्विक सराहना प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह बहुत गर्व की बात है जब हमारे सैनिक भारत की धरती से निर्मित नवाचार की सराहना करते हैं। कई भारतीय स्टार्टअप अब दुबई एयरशो 2025 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भारत की नवोन्मेषण क्षमता पर ध्यान दे रही है।"

रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया कि रक्षा मंत्रालय, स्टार्टअप्स को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ रणनीतिक गठजोड़ कर रहा है।

सीएम योगी का दिवाली तोहफा: सफाईकर्मियों के खाते में अब सीधे 16 से 20 हजार, मिलेगा ₹5 लाख का मुफ्त इलाज

वाराणसी , (जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाईकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है. यह घोषणा उन्होंने वाराणसी के रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच से की. सीएम योगी ने बताया कि ₹16,000 से ₹20,000 प्रति माह सीधे सफाईकर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा. साथ ही, सभी सफाईकर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे. यह घोषणा सफाईकर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए की गई. इस घोषणा से मौजूद सभी सफाईकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

शोषण रुकेगा, सीधा लाभ मिलेगा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी सफाईकर्मी का शोषण नहीं कर पाएगा. 16 से 20 हजार की राशि सीधे प्रत्येक सफाईकर्मी के बैंक अकाउंट में पहुंचेगी.

उन्होंने कहा कि जो लोग सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी सरकार के स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए. इसी कारण, सभी स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त इलाज भी मिलेगा. जीवन में पहली बार इस तरह के सम्मान को पाकर और ऐसी घोषणाएं सुनकर सफाईकर्मी काफी खुश नजर आए.

दीपावली की सार्थक अपील और गुलाब वर्षा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को लेकर एक भावुक अपील भी की. उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली तभी सार्थक है जब पूरे प्रदेश भर के सफाईकर्मियों को मिष्ठान जरूर मिले। हर गरीब के घर में दीपक जलना चाहिए और उसे मिष्ठान का स्वाद भी मिलना चाहिए. सीएम ने कहा कि यही समाज की समरसता है, और उनका काम जोड़ना है, क्योंकि "तोड़ने के लिए पहले से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है."

प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि जयंती पर सभी को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।

श्री मोदी ने प्राचीन काल से ही भारतीय समाज और पारिवारिक जीवन पर महर्षि वाल्मीकि के पवित्र और आदर्श विचारों के गहन प्रभाव का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता पर आधारित महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी राष्ट्र को प्रेरित और आलोकित करती हैं।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा; सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीनकाल से ही हमारे समाज और परिवार पर उनके सात्विक और आदर्श विचारों का गहरा प्रभाव रहा है।

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की

संवाद, विचार-विमर्श, बहस और चर्चा संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं- श्री सी. पी. राधाकृष्णन

संसद सदस्यों से लोक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए शून्यकाल, विशेष उल्लेख और प्रश्नकाल जैसे उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया

भारत का संविधान और राज्यसभा की नियमावली संसदीय विमर्श की लक्ष्मण रेखा निर्धारित करती है - श्री सी. पी. राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति ने लक्ष्मण रेखा के भीतर सभी सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

सदन में हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड का उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए

(जीएनएस)।

माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रियों सहित सदन के 29 नेताओं का स्वागत करते हुए, सभापति ने उनके पदभार ग्रहण करने पर मिले जबर्दस्त समर्थन और शुभकामना संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी हुई कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अल्प सूचना पर एक साथ एकत्रित हुए।

अपने उद्घाटन वक्तव्य में, सभापति ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा गरिमा, अनुशासन और मयार्दा के साथ कार्य करे, जिसकी वह हकदार है। उन्होंने रेखांकित किया कि संवाद, विचार-विमर्श, बहस और चर्चा संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं।

सदस्यों को जन सरोकार के मुद्दे उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों पर प्रकाश डालते हुए, सभापति ने शून्यकाल, विशेष उल्लेख और प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण साधन बताया, जो सदस्यों को तत्काल लोक

महत्व के मुद्दों को उठाने की अनुमति देते हैं।

उन्होंने सदस्यों को याद दिलाया कि भारत का संविधान और राज्यसभा की नियमावली संसदीय विमर्श के लिए मार्गदर्शक ढांचे—लक्ष्मण रेखा—का काम करती है। सभापति ने इस ढांचे के भीतर सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही सदन की पवित्रता बनाए रखने की सभी के साझे दायित्व पर जोर दिया।

उन्होंने सभी सदस्यों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सदन के हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड के समय का उपयोग करने का आग्रह किया।

सदन के माननीय नेता ने विचार साझा किए, जिसके बाद अन्य नेताओं ने भी अपनी बात रखी। सदन के नेता ने सदन की कार्यवाही संचालित करते समय संसदीय प्रक्रिया की उच्च परंपराओं का पालन करने पर जोर दिया और कार्यवाही के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदन चलाने में अपना पूरा सहयोग देने की पेशकश करते हुए माननीय सभापति से अनुरोध किया कि वे विपक्षी दलों को सदन में विभिन्न संसदीय उपायों जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस (पीएमबी), अल्पकालिक चर्चा (एसडीडी), कॉलिंग अटेंशन नोटिस (सीएएन) आदि के माध्यम से अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दें।

कोयला मंत्रालय ने भारतीय कोयला कंपनियों के लिए सीएसआर फ्रेमवर्क संबंधी हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में भारतीय कोयला कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) ढांचे पर विचार-विमर्श हेतु हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की। इस परामर्श बैठक में कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की सीएसआर नीतियां कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के तहत नीति निदेशों के अंतर्गत तैयार की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों से कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, खेल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की हैं। इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए कोयला कंपनियों के लिए एक क्षेत्र-विशिष्ट सीएसआर ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई है, जो ज़िम्मेदार और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के बीच हितधारक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करे।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय की अपर सचिव, सुश्री रूपिंदर बरार ने कोयला कंपनियों से आग्रह किया कि वे समुदाय और व्यवसाय के लाभ के लिए अपने सीएसआर, कल्याण और स्थिरता प्रयासों को एकीकृत करें और उन्होंने इन प्रयासों को मात्रात्मक रूप देकर ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की बात पर जोर दिया।

कोयला क्षेत्र के लिए एक समर्पित सीएसआर ढांचा तैयार करने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने सीएसआर पहलों की योजना बनाते समय स्थानीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सुश्री बरार ने आवश्यकता और प्रभाव आकलन हेतु विश्वसनीय एजेंसियों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि प्रभावी सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु गहन विश्लेषण और कार्यात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके।

ट्राई के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हितधारकों से 6 अक्टूबर 2025 तक टिप्पणियां मांगने के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा 22 सितंबर 2025 को जारी किया था।

कुछ हितधारकों द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं

चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 894 किलोमीटर बढ़ेगा

24,634 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रुपये के परिव्यय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें:

महाराष्ट्र में वर्धा - भुसावल के बीच 314 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन

गुजरात और मध्य प्रदेश में 259 किलोमीटर लंबी वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन

और, मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन शामिल हैं

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों में व्याप्त इन चार परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 894 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी जनसंख्या लगभग 85 लाख 84 हजार है, तथा दो आकांक्षी जिलों, विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ेगा।

लाइन क्षमता में बढ़ोत्तरी से गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा। मल्टी ट्रैकिंग (पटरियों की संख्या बढ़ाना) प्रस्ताव परिचालन सुगम बनाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों का व्यापक विकास होगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनके लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श द्वारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी।

परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हजारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

यह कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न, इस्पात आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए भी आवश्यक मार्ग है। पटरियों की संख्या बढ़ाए जाने से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे के पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण यह देश के जलवायु लक्ष्यों और परिचालन लागत कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) में कमी लाने और कार्बन उत्सर्जन 139 करोड़ किलोग्राम कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

डीआरडीओ ने सैन्य संचार में अंतर-संचालन सक्षमता के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 जारी किया

(जीएनएस)।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन-डीआरडीओ ने एकीकृत रक्षा स्टाफ-आईडीएस और तीनों सेनाओं के सहयोग से, 7 अक्टूबर, 2025 को डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान, सैन्य संचार अंतर-संचालन सक्षमता के लिए भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मानक 1.0 औपचारिक रूप से जारी किया। आईआरएसए, सॉफ्टवेयर युक्त रेडियो का व्यापक सॉफ्टवेयर विनिर्देश है, जो मानकीकृत इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, निष्पादन वातावरण और वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी तंत्र को परिभाषित करता है। आईआरएसए को वेवफॉर्म पोर्टेबिलिटी, एसडीआर इंटरऑपरेबिलिटी, प्रमाणन और अनुरूपता के लिए डिजाइन किया गया है। एसडीआर एक वायरलेस संचार प्रणाली है, जो पारंपरिक हार्डवेयर घटकों को सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामेबल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म से प्रतिस्थापित करती है, जिससे सिग्नल मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन जैसे स्थिति अनुरूप और गतिशील रेडियो फंक्शन संभव होते हैं।

आईआरएसए का शुभारंभ रक्षा संचार प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है,

जो स्वदेशी, अंतर-संचालनीय और भविष्य के लिए तैयार एसडीआर समाधानों के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है। इसे स्वदेशी तौर पर भारत के लिए और वैश्विक प्रयोग हेतु तैयार किया गया है। इसे परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है जो भविष्य की प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करेगा।

कार्यशाला में आईआरएसए की यात्रा, इसके तकनीकी अवलोकन, पारिस्थितिकी तंत्र भूमिकाओं और इसकी भविष्य रूपरेखा पर चर्चा हुई। इसमें उद्योग, शिक्षा जगत और तीनों सेनाओं के सहयोग अवसरों, अग्रिम परियोजनाओं और तकनीक अपनाने के तौर-तरीकों पर विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बलों, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और स्वदेशी संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। डीडी आरएंडडी सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और आईआईटी गांधीनगर के निदेशक डॉ. रजत मूना विशिष्ट अतिथि थे।

आईआरएसए के बारे में:

आधुनिक सैन्य संचार में एसडीआर की महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर मानक की आवश्यकता पर आईआरएसए पहल 2021 में आरंभ हुई थी। डीआरडीओ के नेतृत्व में एक प्रमुख तकनीकी टीम ने 2022 में एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेनाओं के साथ मिलकर परिचालन और उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को समझने के लिए विमर्श आरंभ किया। हितधारकों के साथ व्यापक समीक्षा और परामर्श के बाद, आईआरएसए संस्करण 1.0 को 2025 में उच्च-स्तरीय सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जो सॉफ्टवेयर युक्त रेडियो के लिए एक मानकीकृत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर परिभाषित करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय विनिर्देश बना। इसका उद्देश्य आईआरएसए को राष्ट्रीय मानक के साथ ही वैश्विक मानदंड के रूप में स्थापित करना है जिससे भारत एसडीआर की नवीनतम तकनीक विकसित कर मित्र देशों को भी आईआरएसए-अनुरूप समाधान निर्यात कर सके।

आईटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धारा 69ए और 79(3)(बी) के तहत शक्तियों का विवेकपूर्ण और स्पष्ट प्रयोग जरुरी है: श्री एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

79(3)(बी) के तहत मध्यस्थों को जारी किए जाने वाले नोटिस मानकीकृत होने चाहिए और उनमें प्रासंगिक कानूनी प्रावधान, स्पष्टता और एकरूपता जैसे जरुरी तत्व शामिल होने चाहिए, ताकि गैरकानूनी सूचनाओं पर अंकुश लगाया जा सके

मध्यस्थों को दिए जाने वाले नोटिसों को सुव्यवस्थित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर सूचना प्रबंधन" पर कार्यशाला का आयोजन किया

नोटिस प्रारूपों के मानकीकरण, स्पष्टता, एकरूपता और सरकार भर में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञ एक मंच पर हुए एकत्रित

(जीएनएस)।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से विकास के चलते, आईटी मध्यस्थों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी सूचनाओं में वृद्धि हुई है। इन गैरकानूनी सूचनाओं पर लगाम कसने के लिए, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) और आईटी नियम 2021 के नियम 3(1)(डी), संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी सूचनाओं को हटाने या उन तक पहुँच को अक्षम करने के लिए, आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने का अधिकार देते हैं।

इस बावत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 7 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में मध्यस्थ प्लेटफॉर्म पर सूचना प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस

कार्यशाला का मकसद प्रतिभागियों को आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों, खास तौर पर धारा 69ए और 79(3)(बी) और नियम 3(1)(डी) के बारे में संवेदनशील बनाना और जिम्मेदार डिजिटल शासन और प्रभावी सामग्री प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद करना था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए और 79(3)(बी) के दायरे और उद्देश्य पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि धारा 69ए सरकार को, अपनी कार्यकारी क्षमता में, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा पैदा करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। दूसरी ओर, धारा 79, मध्यस्थों को उनके दायित्वों और अनुपालन न करने की स्थिति में संभावित दायित्व के बारे में सूचित करती है, हांलाकि अंतिम फैसला न्यायपालिका के पास रहता है।

उन्होंने एक उपयुक्त प्रारूप की जरुरत पर भी जोर दिया और कहा कि धारा 79(3)(बी) के तहत, धारा 69ए के समान निर्देश/आदेश वाले नोटिसों से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रावधानों का दायरा पूरी तरह से अलग है। भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षक के रूप में, यथोचित सरकार या उसकी एजेंसी को शक्तियों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि वे न्यायिक जाँच का सामना कर सकें और भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन भी बना रहे।

अपने स्वागत भाषण में संयुक्त सचिव (साइबर कानून) श्री अजीत कुमार ने फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की वजह से बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नोटिसों में होने वाली कमियाँ, अक्सर न्यायिक चुनौतियों का कारण बनती हैं, लिहाजा उन्हें तैयार करते समय एक व्यापक और मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरुरत है।

कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण नोटिस तैयार करने के लिए एक मानकीकृत प्रारूप अपनाने पर सरकारी विभागों के बीच आम सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया, जिससे कार्यान्वयन में अधिक स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

इस कार्यक्रम में भारतीय अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), विधिक कार्य विभाग (डीओएलए), भारतीय सेना, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विषय विशेषज्ञ तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। सरकार ने सभी हितधारकों से मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन करने और स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नोटिसों में जरुरी तत्वों को शामिल करने की अपील की।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

(जीएनएस)।

भारत के सबसे बड़े छात्र नवाचार आंदोलन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए देश भर के छात्र 11 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है। यह देश भर के लगभग ढाई लाख स्कूलों के छात्रों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी छात्र नवाचार पहल है और विकसित भारत @2047 के विजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

छात्र नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए स्कूल अपनी प्रविष्टियाँ फोटो और वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। विशेषज्ञों का एक पैनल प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगा और शीर्ष टीमों को 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मान्यता के अलावा, इन स्कूलों और छात्रों को कॉपोरेट स्वीकृति, मार्गदर्शन और

संसाधनों के माध्यम से दीर्घकालिक समर्थन प्राप्त होगा ताकि उनके नवाचारों को और मजबूत किया जा सके।

बिल्डथॉन की मुख्य विशेषताएँ:

इदेश भर के छात्र दुनिया की सबसे बड़ी लाइव नवाचार गतिविधि में एक साथ नवाचार करेंगे

इराष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप व्यावहारिक, अनुभवात्मक शिक्षा

इआकांक्षी ज़िलों, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ समावेशी भागीदारी

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 छात्रों को बड़े सपने देखने, निडर होकर नवाचार करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान देने का आ'ान करता है। प्रत्येक स्कूल और प्रत्येक छात्र को इस आंदोलन में शामिल होने और अपनी प्रतिभा दिखाने तथा भविष्य के नवप्रवर्तकों के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

बिल्डथॉन कक्षा 6 से 12 के छात्रों से टीमों में शामिल होने, रचनात्मक रूप से सोचने और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रतिमान विकसित करने का आ'ान करता है। छात्र राष्ट्रीय महत्व के चार विषयों पर काम करेंगे:

रक्षा और सुरक्षा पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है और रक्षा सेक्टर को सुदृढ़ करना केवल एक संस्थान या सरकार का कर्तव्य नहीं, बल्कि सभी भारतीयों का साझा संकल्प है: रक्षा मंत्री

रक्षा में आत्मनिर्भरता हमारे लिए केवल उत्पादन या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं, यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है और यह सीधे हमारी संप्रभुता से जुड़ा हुआ है

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने की अपील की।

'मंत्रालय निवेश, प्रौद्योगिकी अवशोषण और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डीएपी 2020, डीपीएम 2025, रक्षा ऑफसेट नीति और रक्षा निवेशक सेल जैसे ढांचे को लगातार परिष्कृत कर रहा है'

चाहे वह आईडेक्स पहल हो, रक्षा गलियारों की स्थापना हो या रक्षा विनिर्माण में एफडीआई को बढ़ावा देना हो, सरकार ने स्वदेशीकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं: रक्षा मंत्री

भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात अर्जित करना है: रक्षा मंत्री

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 07 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, "रक्षा और सुरक्षा पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है और रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना केवल एक संस्थान या सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि सभी भारतीयों का साझा संकल्प है।" 'देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर' विषय पर आयोजित कार्यक्रम के तहत, रक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक मजबूत, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने की अपील की।

श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारे लिए सिर्फ. उत्पादन या अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है और सीधे तौर पर संप्रभुता से जुड़ा है। उन्होंने रेखांकित किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब देश को मॉक ड्रिल की जरूरत थी, सभी राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा, "यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब हम सभी मिलकर किसी लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।"

भारत का बढ़ता रक्षा उद्योग

रक्षा मंत्री ने पिछले दशक में भारत के रक्षा विनिर्माण सैक्टर की अभूतपूर्व वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन, जो 2014 में 46,000 करोड़ रुपये से अधिक था, अब 2025 में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि 33,000 करोड़ रुपये से अधिक निजी क्षेत्र से आता है, जो स्पष्ट संकेत है कि उद्योग आत्मनिर्भरता मिशन में एक समान हितधारक बन गया है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2014 में 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में रिकॉर्ड 23,500 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने रेखांकित किया, "रक्षा उपकरणों के विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक होने से लेकर रक्षा प्रणालियों के एक विश्वसनीय निर्यातक बनने तक की यह उल्लेखनीय यात्रा हमारे राष्ट्रीय संकल्प का प्रमाण है।"

2029 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य: आत्मनिर्भर भारत की तेज गति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन की पुष्टि करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात अर्जित करना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल मेक इन इंडिया या निर्यात के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस आत्मविश्वास का विषय है कि संकट के समय में हम अपनी रक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए आत्मविश्वास की बात है कि हमारे सशस्त्र बल जिन अस्त्रों का उपयोग करते हैं, वे हमारी अपनी धरती पर निर्मित हैं और हमारे अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रतिभा से सृजित हैं।"

राज्य नीतियों का संग्रह जारी

रक्षा मंत्री ने रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण पर राज्य नीतियों का एक संग्रह जारी किया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई नीतियों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का समावेश है। श्री राजनाथ सिंह ने इस दस्तावेज को केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर नीतिगत संयोजन और समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा, "यह संकलन उद्योग जगत और नवप्रवर्तकों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह करता हूँ कि वे इसका गहराई से अध्ययन करें, इसकी खूबियों को समझें और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को लागू करें।" उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज रक्षा निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारतीय नौसेना की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता -'थिंक 2025'अब क्षेत्रीय चयन दौर की ओर बढ़ रही है

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना की प्रश्नोत्तरी झ थिंक 2025 ने रोमांचक एलिमिनेशन राउंड के साथ एक महत्वपूर्ण चरण पूरा किया है। देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित 166 टीमें अब 13 और 14 अक्टूबर, 2025 को होने वाले क्षेत्रीय चयन दौर में हिस्सा लेंगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले नवंबर 2025 की शुरूआत में एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में आयोजित होगा।

दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय (एचक्यूएसएनसी) के तत्वावधान में आयोजित यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भारतीय नौसेना की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य देशभर के युवाओं में जिज्ञासा, ज्ञान एवं बौद्धिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है और साथ ही समुद्री

चेतना तथा राष्ट्र के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

इस प्रतियोगिता की शुरूआत 08 सितंबर, 2025 को एलिमिनेशन राउंड-क (ईआर-क) से हुई थी, जिसमें देशभर के स्कूलों से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने इस चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता में अपने संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए विविध विषयों पर अपनी जागरूकता, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

तीन सप्ताह से अधिक समय तक चले एलिमिनेशन राउंड का समापन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के चयन के साथ हुआ। ये विद्यालय अब 13 और 14 अक्टूबर 2025 को प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय चयन दौर में भाग लेंगे। देशभर से कुल 166 टीमों ने क्षेत्रीय चरण के लिए अर्हता प्राप्त की है।

थिंक न केवल उत्कृष्टता को प्रेरित करने वाले एक सशक्त मंच के रूप में टीम वर्क और प्रतिस्पर्धी भावना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह प्रतिभागियों में भारतीय नौसेना की गौरवशाली समुद्री विरासत के प्रति आवश्यक जानकारी को फैलाता भी है।

यह पहल युवाओं से जुड़ने, उनमें नेतृत्व क्षमता और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नौसेना की दृढ़ वचनबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

यह प्रतियोगिता अब रोमांचक सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले की ओर आगे बढ़ रही है, जो नवंबर 2025 की शुरूआत में एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए) में आयोजित होंगे। यहां देश के प्रतिभाशाली युवा प्रश्नोत्तरी थिंक 2025 चैंपियंस के गौरवशाली खिताब के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करेंगे।

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 को छात्रों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने युवा इनोवेटर्स को आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्डथॉन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है, जिसे छात्रों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है और इसमें देश भर के लगभग 2.5 लाख स्कूलों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी छात्र नवाचार पहल है और विकसित भारत के विजन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

इस पहल को बढ़ावा देते हुए, भारतीय वायु सेना के टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री तथा विकसित भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एंबेसडर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने वीडियो संदेश में छात्रों से इस पहल में शामिल होने और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने का आग्रह किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिल्डथॉन कक्षा 6-12 के छात्रों को रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हर विचार, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, विकसित भारत 2047 को आकार देने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अभिनव ढंग से सोचना चाहिए और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रोटोटाइप विकसित करने चाहिए, जिसमें वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी की क्षमता का उपयोग करना शामिल है।

स्कूल फोटो और वीडियो के माध्यम से प्रविष्टियां प्रस्तुत करेंगे, जिनका मूल्यांकन एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाएगा। शीर्ष पर रहने वाली टीमों को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर हो रही चौंकाने वाली चर्चा

बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियां अपने चरम पर हैं। कांटे की टक्कर दिखती है बिहार में, पार्टियों के बीच साधे जा रही सीटों के समीकरण के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईआर यानि गहन मतदाता पुनरीक्षण के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बिहार में अब 7.42 करोड़ मतदाता हैं। अब बिहार चुनाव की घोषणा भी हो गईं और 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट भी आ जाएगा। पाठकों की जानकारी के लिए बिहार में विधानसभा की वुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है। बिहार में फिलहाल जेडीयू और भारतीय जनता पाटा (भाजपा) के घटक दलों वाली एनडीए सरकार है और आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रातिपक्ष हैं। विधानसभा में अभी भाजपा के 80 विधायक हैं। आरजेडी के 77, जेडीयू के 45 और कांग्रोस के 19, कम्युनिस्ट पाटा के 11, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) के 4, कम्युनिस्ट पाटा (मार्क्सवादी) के 2, कम्युनिस्ट पाटा आफ इंडिया के दो, ओवैसी की पाटा का एक और 2 निर्दलीय विधायक हैं। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जमकर रेविड़यां बांट रही है। कहीं तो बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच रहे हैं तो कहीं चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले सीएम नीतीश वुमार की तरफ से करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा हो रही है। महिलाओं के खातों में पैसे देने के बाद पीएम मोदी ने युवाओं के लिए करीब 62 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। इनमें बिहार के लिए भी काफी योजनाएं हैं। इन योजनाओं से लगता है कि बिहार चुनाव सत्तारूढ़ वेंद्र की एनडीए सरकार के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है और वेंद्रीय नेतृत्व किसी भी हालत में बिहार खोना नहीं चाहता। इन योजनाओं से लगता है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश वुमार महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देकर चुनाव में जीत की संभावनाएं बढ़ाने का प्रायास कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।

एसआईआर, वोट चोरी और संविधान रक्षा इनके प्रामुख मुद्दे हैं। एनडीए की अंदरूनी खींचतान भी चिता का विषय बना हुआ है। इस बार चुनाव में एक नया पैक्टर भी जुड़ गया है। वह है पीके यानि प्राशांत किशोर और उनकी जन सुराज पाटा। पीके ने बिहार में अपने आरोपों से तहलका मचा दिया है।

उनके फिलहाल निशाने पर सत्तारुढ़ एनडीए सरकार के मंत्री हैं। प्राशांत किशोर अपनी जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ खींच रहे हैं। देखना यह होगा कि यह किसकी वोट काटते हैं, एनडीए की या महागठबंधन की? अगर पीके 10-12 सीटें निकाल लेते हैं तो यह किग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। बिहार में इस समय लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम जन सुराज पाटा के बीच दिखती है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चुनाव पूर्व सव्रेक्षणों पर विश्वास नहीं करता पर जो इन पर यकीन करते हैं उनकी जानकारी के लिए एक ताजा सव्रेक्षण का ब्यौरा दे रहा हूं। नीतीश वुमार, तेजस्वी या प्राशांत किशोर.. बिहार का कौन होगा अगला मुख्यमंत्री नाम के सी-वोटर का ताजा सव्रेक्षण आया है। 2025 में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। हालिया सी-वोटर सव्रे ने दिखाया है कि तेजस्वी यादव अभी सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्राशांत किशोर ने लोकप्रिया में नीतीश वुमार को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन जीत रहा है यह कहना मुश्किल है, कांटे की टक्कर है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और प्राशांत की जन सुराज पाटा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले ने लड़ाई दिलचस्प बना दी है। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश वुमार लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर एनडीए की जीत होती है तो क्या भाजपा किसी नए मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करेगी। वहीं विपक्ष अगर जीतती है तो उसका कौन मुख्यमंत्री होगा क्योंकि अभी तक इस विषय पर कांग्रोस ने वुछ खुलकर नहीं बोला है।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की सफल सर्वग्राही विकास यात्रा के 24 वर्षों की सफलता का जश्न मनाने के लिए 'विकास सप्ताह' का प्रारंभ

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सचिवों एवं पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव की सामूहिक 'भारत विकास प्रतिज्ञा'ली

गांधीनगर, 07 अक्टूबर : श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अक्टूबर, 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर राज्य की विकास यात्रा को एक नया आयाम दिया था।

उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात की 2001 से 2025 तक की 24 वर्षों की सर्वग्राही वैश्विक विकास यात्रा की सफलता गाथा में जनभागीदारी के साथ 7 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले 'विकास सप्ताह'के जश्न की शुरूआत 'भारत विकास प्रतिज्ञा'से हुई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ सचिवों एवं पदाधिकारियों ने विधानसभा पोडियम में आयोजित सामूहिक प्रतिज्ञा पठन कार्यक्रम में शामिल होकर 'भारत विकास प्रतिज्ञा'ली।

देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प किया है, उसे साकार करने में अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए सभी लोगों ने मन, वचन और कर्म से तत्पर रहने के साथ ही देश के प्रति समर्पण भाव की सामूहिक भारत विकास प्रतिज्ञा की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रियों और मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी एवं वरिष्ठ सचिवों द्वारा ली गई 'भारत विकास प्रतिज्ञा'इस प्रकार है:-

मैं भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रतिज्ञा करता हूँ कि...

- मैं अपने जीवन के हर पल में देश के लिए समर्पित रहूँगा।
- मैं स्वयं के बारे में सोचने से पहले दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करूंगा। मैं देश के सभी संसाधनों का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करूंगा। मैं देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए निःस्वार्थ भाव से निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
- मैं अपने देश की समृद्ध परंपरा और विरासत पर गर्व अनुभव करूंगा तथा उसे संरक्षित रखने का निरंतर प्रयास करूंगा।
- मैं अपने देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा और उनके संरक्षण में योगदान दूंगा।
- मैं जाति, धर्म या वर्ण के सभी बंधनों से मुक्त होकर, बंधुता और एकता की भावना के साथ अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्श को साकार करने हेतु भारत की एकता और अखंडता की रक्षा में निरंतर प्रयासरत रहूंगा।
- मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए अपने मन, वचन और कर्म से निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा।
- "हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी" के आदर्श को अपनाकर, मैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देने का प्रयास करूंगा।
- 'राष्ट्र प्रथम' को अपने जीवन का मूलमंत्र बनाकर, मैं अपने देश के विकास और कल्याण हेतु तन, मन और धन से सतत कार्य करता रहूंगा।

विकास सप्ताह के जश्न के अंतर्गत भारत विकास प्रतिज्ञा ऑनलाइन तरीके से भी ली जा सके, इस उद्देश्य से पोर्टल- https://pledge.mygov.in/bharat-vikas/ शुरू किया गया है। राज्य के नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं और प्रतिज्ञा लेकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए भारत के पहले एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप- "मुंबई वन" की शुरूआत करेंगे

प्रधानमंत्री 8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे और 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से निर्मित संपूर्ण मुंबई मेट्रो लाइन-3 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रारंभ की जा रही परियोजनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु: निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है

भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी और विजन 2035 रोडमैप की समीक्षा करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में मुख्य संबोधन देंगे

जीएफएफ 2025 का विषय: एआई, संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार और समावेश द्वारा संचालित

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8-9 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई पहुंचने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात, लगभग 3:30 बजे प्रधानमंत्री नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और समर्पित भी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

9 अक्टूबर को सुबह लगभग 10 बजे, प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर की मेजबानी करेंगे। दोपहर लगभग 1:40 बजे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 2:45 बजे, दोनों प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में

शामिल होंगे। वे फेस्ट में मुख्य संबोधन भी देंगे।

नवी मुंबई में प्रधानमंत्री

भारत को वैश्विक विमानन केंद्र में परिवर्तित करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, प्रधानमंत्री लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के चरण 1 का उद्घाटन करेंगे।

नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में, एनएमआईए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर कार्य करेगा ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को वैश्विक बहु-हवाई अड्डा प्रणालियों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। 1160 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ, दुनिया के सबसे कुशल हवाई अड्डों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया यह हवाई अड्डा अंततः वार्षिक 90 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाल सकेगा।

इसकी अनूठी सुविधाओं में एक स्वचालित पीपल मूवर (एपीएम) शामिल है, जो एक परिवहन प्रणाली है जो सभी चार यात्री टर्मिनलों को सुचारू अंतर-टर्मिनल स्थानांतरण के लिए जोड़ेगी, साथ ही एक लैंडसाइड एपीएम भी है जो शहर के बुनियादी ढांचे को जोड़ेगा। स्थायी प्रथाओं के अनुरूप, इस हवाई अड्डे में स्थायी विमानन ईंधन (एसएएफ) के लिए समर्पित भंडारण, लगभग 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन और पूरे शहर में सार्वजनिक संपर्क के लिए ईवी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। एनएमआईए देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ा होगा।

प्रधानमंत्री आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक फैली मुंबई मेट्रो लाइन-3 के चरण 2बी का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण लगभग 12,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हुआ है। इसके साथ ही, वह 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत वाली पूरी मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यह शहरी परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।

मुंबई की पहली और एकमात्र पूर्णतः भूमिगत मेट्रो लाइन के रूप में, यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आवागमन को नए सिरे से परिभाषित करेगी, तथा लाखों निवासियों के लिए एक तीव्र, अधिक कुशल और आधुनिक परिवहन समाधान प्रदान करेगी।

कफ परेड से आरे जेवीएलआर तक 33.5 किलोमीटर लंबी, 27 स्टेशनों वाली मुंबई मेट्रो लाइन-3 प्रतिदिन 13 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी। इस परियोजना का अंतिम चरण 2बी, दक्षिण मुंबई के विरासत और सांस्कृतिक जिलों जैसे किला, काला घोड़ा और मरीन ड्राइव तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायालय, मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नरीमन पॉइंट सहित प्रमुख प्रशासनिक और वित्तीय केंद्रों तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

मेट्रो लाइन-3 को रेलवे, हवाई अड्डों, अन्य मेट्रो लाइनों और मोनोरेल सेवाओं सहित परिवहन के अन्य साधनों के साथ कुशल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और महानगरीय क्षेत्र में भीड़-भाड़ कम होगी।

प्रधानमंत्री मेट्रो, मोनोरेल,

प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे

आईएमसी 2025: एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा

विषय: "परिवर्तन के लिए नवाचार"- डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना

केंद्रित क्षेत्र: 6 जी, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम

आईएमसी 2025 में 400 से अधिक कंपनियां, लगभग 7,000 वैश्विक प्रतिनिधि और 150 से अधिक देशों के लगभग 1.5 लाख आगंतुक शामिल होंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को प्रातः लगभग 9:45 बजे यशोभूमि, नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आईएमसी 2025 का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक "इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म" विषय के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए नवाचार का लाभ उठाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जाएगा।

आईएमसी 2025 दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक प्रमुखों, नीति निमार्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को एक साथ एक मंच पर लाएगा। यह कार्यक्रम ऑप्टिकल संचार, दूरसंचार में सेमीकंडक्टर, क्वांटम संचार, 6जी और धोखाधड़ी जोखिम संकेतक जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा, जो अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी, डिजिटल संप्रभुता, साइबर धोखाधड़ी रोकथाम और वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व में भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दशार्ता है।

इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा देशों से 1.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों, 7,000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधियों और 400 से ज्यादा कंपनियों के भाग लेने की आशा है। 5जी/6जी, एआई, स्मार्ट मोबिलिटी, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 1,600 से ज्यादा नए उपयोग-मामलों को 100 से ज्यादा सत्रों और 800 से ज्यादा वक्ताओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

आईएमसी 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी बल देता है, जिसमें जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी ने जैव सुरक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान की साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया

पांच दिवसीय जैव सुरक्षा कार्यशाला ने सीसीआरएच के वैज्ञानिकों को सशक्त बनाया, सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में भारत की प्रतिक्रिया में वृद्धि

एमएएचई में नये प्रकार के जैव सुरक्षा प्रशिक्षण ने होम्योपैथी शोधकताओं को उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया

विशेष जैव सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए 14 राज्यों के 30 सीसीआरएच वैज्ञानिकों का चयन

अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीसीआरएच और एमएएचई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

कार्यशाला ने होम्योपैथी वैज्ञानिकों को संक्रामक रोगों और महामारी के संबंध में प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) ने मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी (एमएएचई), मणिपाल की घटक इकाई, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एमआईवी) के सहयोग से 6 से 10 अक्टूबर, 2025 तक एमएएचई परिसर, मणिपाल, कर्नाटक में 'जैव सुरक्षा और प्रकोप सिमुलेशन प्रशिक्षण 2025' शीर्षक पांच दिवसीय आवासीय कार्यशाला शुरू की है।

यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सीसीआरएच के अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत सटीक रूप से तैयार किया गया है। इस क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य तैयारियों, जैव सुरक्षा प्रथाओं और रोगों के प्रकोप की स्थिति में प्रतिक्रिया की क्षमताओं को बढ़ाना है जिससे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संबंधी पहलों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

सीसीआरएच के अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण के इस अवसर ने भारत के 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीसीआरएच के 33 संस्थानों/इकाइयों की व्यापक भागीदारी के साथ बड़े स्तर पर रुचि पैदा की है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ओर से किए गए गहन ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 30 प्रतिभाशाली अनुसंधान वैज्ञानिकों का चयन किया गया।

गणमान्य व्यक्ति और सीसीआरएच अनुसंधान वैज्ञानिक

एमआईवी के निदेशक डॉ. चिरंजय मुखोपाध्याय ने कार्यशाला में सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं का स्वागत किया। सीसीआरएच के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में सामर्थ्यवान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण और अनुसंधान वैज्ञानिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरते संकटों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के उद्देश्य से सीसीआरएच और एमएएचई के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों से निपटने में होम्योपैथी की क्षमता का उल्लेख किया।

इस दौरान, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रमुख क्षेत्रों में उपयोगी सहयोग को सुगम बनाने के लिए सीसीआरएच और एमएएचई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। सीसीआरएच के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक और एमएएचई के रजिस्ट्रार डॉ. पी. गिरिधर किनी ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सीसीआरएच और एमएएचई के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

इसके अतिरिक्त, एमएएचई में स्वास्थ्य विज्ञान के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. शरत कुमार राव के. ने अपने मुख्य भाषण में इस प्रशिक्षण के आयोजन के प्रयासों की सराहना की और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन में एमएएचई की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया।

सीसीआरएच में अनुसंधान अधिकारी (होम्योपैथी)/वैज्ञानिक-द्वितीय डॉ. सुहाना पी. अजीस, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्रीकांत गोपीनाथन पिल्लई, सहायक प्रोफेसर डॉ. सुधीश एन., और एमआईवी, मणिपाल के व्याख्याता श्री अनुप जयराम इस प्रशिक्षण के समन्वयक थे।

जम्मू-कश्मीर के आपदा प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार से मिली राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पीएम-किसान की 21वीं किस्त अग्रिम जारी

जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि के 171 करोड़ रु. जमा

कृषि भवन, दिल्ली में सादे समारोह में श्री शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह हुए शामिल

अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान के तहत 4,052 करोड़ रु. दिए जा चुके- श्री शिवराज सिंह

प्रभावित जनता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं- श्री शिवराज सिंह

5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 85 करोड़ रु. का बजट भी मंजूर- श्री शिवराज सिंह

मनरेगा के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

आपदा के इस समय में अन्य सभी प्रकार से भी हरसंभव सहायता की जाएगी- श्री शिवराज सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि भवन, नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ व भूस्खलन प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम जारी की। इस सादे समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, वहीं जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री श्री जावेद अहमद डार, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। आज की किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान के तहत अब तक कुल 4,052 करोड़ रु. की सहायता दी जा चुकी है।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदा से प्रभावित जम्मू-कश्मीर के किसानों के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, हम सभी प्रभावित किसानों व अन्य लोगों को संकट से पार निकालेंगे, इसी कड़ी में एक कदम पीएम-किसान की किस्त की यह राशि बड़ी राहत है, जिससे किसान अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम किसी भी किसान को संकट की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे।

बाल्मिक जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, भगवान श्री राम, सीता मैया, हनुमान जी वाल्मीकि जी की झांकियां निकाली गईं।

(जीएनएस)।

पीलीभीत पूरनपुर। देश प्रदेश में बाल्मिक जयंती समारोह बहुत ही धार्मिक और भव्य अंदाज में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि के जीवन तथा उनके आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान को दशार्ती सुंदर-सुंदर झांकियां सजाई और प्रस्तुत की गईं। इन झांकियों में वाल्मीकि रामायण की कथा, उनका संतत्व, संस्कृत भाषा के प्रति उनका योगदान और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को जीवंत रूप से दिखाया गया।

महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि जी को उनकी विद्वता और तपस्या के कारण महर्षि की उपाधि मिली थी। उन्होंने रामायण जैसे महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना की और उन्हें संस्कृत के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है।

पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विम माह की पूर्णिमा तिथि पर वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। ऐसे में आज 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती मनाई गई। उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया रामायण महाकाव्य हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है।

पीलीभीत जनपद के विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत पिपरा मुजप्ता में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के आयोजक धर्मवीर वाल्मीक, अमन कीर्तन शुक्ला, फतेह चन्द्र शुक्ला, प्रधान विनोद कुमार प्रजापति, सतीश शर्मा, आनन्द पासवन, (पत्रकार) मंजीत शर्मा, सुधीर, रमेश, सुरेश, शिवा, किशन, सूरज, विकास, सत्यदेव कुशवाहा, बलवीर कुशवाहा, रामगोपाल चौहान, सूरज सूर्यवंशी, राजू, अनिल, श्रीपाल आदि ग्राम वासी सम्मिलित हुए।

समारोह में बच्चों एवं ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्व को और भी खास बना दिया। आयोजन के दौरान सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें वाल्मीकि जी की शिक्षाओं को गीत-नृत्य के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। लगभग सभी वर्ग के लोग श्रद्धा भाव से इस पुण्य दिवस में शामिल हुए और उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा ली।

बदायूं के नगर सैदपुर में निकाला गया संघ का भव्य पथ संचलन

सैदपुरः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नगर सैदपुर में आयोजित भव्य पथ संचलन सोमवार को वजीरगंज की कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। पथ संचलन के आगे-आगे पुलिस कर्मी चल रहे थे। दंड और पूर्ण गणवेश में पथ संचलन का शुभारंभ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से होते हुए कौआ टोला, मोहल्ला कुरैशियान , मैन रोड, मोहल्ला खांची होते हुए वापस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पर समाप्त हुई। रास्ते में स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा का स्वयंसेवकों का स्वागत किया। जिला प्रचारक ने कहा कि संघ का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देना है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण व परिवार प्रबोधन विषयों को स्वयंसेवकों के व्यवहार में

लाया जाता है। नगर संघ चालक कृपाशंकर शर्मा, नगर कार्यवाह वेदप्रकाश माहेश्वरी, जिला सह संयोजक एबीवीपी आशीष देव मिश्रा, नगर शारीरिक प्रमुख हिमांशु पाराशरी, व्यवस्था प्रमुख यश माहेश्वरी,मोहित शर्मा नंदेश्वर दयाल आदि लोग उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस की सराहनीय पहल : दम्पतियों की काउंसलिंग कर कराया पुनर्मिलन, गुमशुदा बच्ची को सकुशल किया बरामद

(जीएनएस)।

बाराबंकी। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए संचालित 'मिशन शक्ति फेज-05' के तहत जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक सौहार्द की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जनपद के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की महिला अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों की महिलाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।थाना टिकैतनगर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम नूरवाफ कस्बा टिकैतनगर निवासी दम्पति, जो आपसी मतभेद के चलते अलग रह रहे थे, की काउंसलिंग प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुमार शुक्ला के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति सहायता केन्द्र की टीम — उप निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह, महिला आरक्षी प्रिया सिंह एवं ज्योति देवी द्वारा की गई। काउंसलिंग के उपरांत दोनों पक्ष आपसी सहमति से पुनः साथ रहने को तैयार हुए। इसी प्रकार थाना मसौली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम

बांसा निवासी दम्पति, जो आपसी विवाद के चलते अलग रह रहे थे, की काउंसलिंग प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह के पर्यवेक्षण में अतिरिक्त निरीक्षक सनत कुमार मिश्रा एवं महिला आरक्षी किरन द्वारा की गई।

काउंसलिंग के पश्चात दोनों पति-पत्नी ने आपसी मतभेद समाप्त कर पुनः साथ रहने की सहमति दी।वहीं थाना देवा क्षेत्र में महिला सुरक्षा दल एवं पीआरवी 5050 के संयुक्त प्रयास से गुमशुदा बच्ची अलीजा पुत्री सकीउल्ला निवासी कर्बला कस्बा देवा को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्ची अपने परिजनों के साथ सीएचसी देवा गई थी, जहां से वह गुम हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर बच्ची को सुरक्षित खोज निकाला। मिशन शक्ति फेज-05 के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा किए जा रहे ये प्रयास महिलाओं की सुरक्षा एवं सामाजिक समरसता की दिशा में एक सराहनीय कदम हैं।

रिश्ते की आड़ में 26 लाख की ठगी, पंचायत में दी जान से मारने की धमकी

पीलीभीत, सेवानिवृत्त कर्मचारी को रिश्ते का भरोसा इतना भारी पड़ गया कि ज़िंदगी की कमाई ही लुटा बैठा। मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव जिरौनियां निवासी बुद्धसेन ने अपने साले के बेटे पर 26 लाख रुपये की ठगी और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी पंचायत में खुलेआम बोल गय, कि अब कोई रिश्ता नहीं, जो करना हो कर लो... पैसा नहीं मिलेगा,पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह एक सरकारी गोदाम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और मई 2022 में सेवानिवृत्त हुआ। उसे लगभग 41 लाख रुपये फंड के रूप में मिले थे। उसी दौरान उसका करीबी रिश्तेदार रमेश पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम कनपरी (थाना बिलसंडा) अक्सर घर आता-जाता था। वह टेंट व्यवसायी है और यही कहकर उसने कहा—'फूफा जी, बारातों का सीजन है, टेंट का सामान लेना है, दो महीने में पैसे लौटा दूंगा। 26 लाख दिए, लौटाए सिर्फ 5 लाख, अब मुकर गया।भरोसे में आकर पीड़ित ने 18 जुलाई 2022 से 7 अक्तूबर 2022 के बीच अपने बैंक खाते से 26 लाख 8 हजार रुपये रमेश को दे दिए। तय समय पर पैसे नहीं लौटाए गए। बार-बार तकादा करने पर 5 लाख 4 हजार रुपये पीड़ित की पुत्रवध के खाते में भेजे, बाकी पैसे डकार गया।पंचायत में बोला, हम पैसे हड़प चुके हैं, भूल जाओ! 15 मई 2024 को जब इस मामले को लेकर कनपरी गांव में पंचायत बैठी,तो वहां आरोपी रमेश ने साफ कहा—'हम पैसे नहीं देंगे, जो करना हो कर लो, रिश्तेदारी भूल जाओ, यही नहीं, धमकी भी दी कि दोबारा पैसे मांगे तो जान से हाथ धो बैठोगे।पीड़ित ने उसी दिन थाना बिलसंडा में तहरीर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन्होंने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।आरोपी रमेश पर पूर्व में भी बीसलपुर थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और ठगी के एक मामले में चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय में भी दर्ज हो चुका है। कई किसानों से प्लाट देने के नाम पर ठगी कर चुका है,ऐसे में पीड़ित ने आशंका जताई है कि यह कोई पहला मामला नहीं बल्कि आरोपी आदतन ठग है। अब देखना है कि पुलिस इस बार भी चुप रहती है या रिश्ते की आड़ में हो रही इस खुलेआम लूट पर सख्त कार्रवाई करती है।

ग्राम पंचायत दुर्जनपुर कला नजीरगंज में मौलाना द्वारा सामाजिक सौहार्द भंग करने की कोशिश, ग्रामीणों में गुस्सा

(जीएनएस)।

पीलीभीत:तहसील पूरनपुर की ग्राम पंचायत दुर्जनपुर कला नजीरगंज की मस्जिद में एक मौलाना पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने गांव में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। वायरल हुए वीडियो में मौलाना नाबालिग बच्चों को लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं और उन्होंने 80 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक पर रखने जैसी विवादास्पद बातें की हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले कभी गांव में ऐसा तनावपूर्ण माहौल नहीं बन पाया था। सूत्रों से पता चला है कि इस घटना में शामिल सभी लोग एक समुदाय नजीरगंज के ही हैं। इस कृत्य के खिलाफ ग्रामीण गुस्से में हैं और हिंदू संगठनों ने भी मौलाना के इस व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि सामाजिक शांति बनी रहे।

लंबित मामलों पर गृह मंत्रालय सक्रिय भागीदार के तौर पर विशेष अभियान चला रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छता को संस्थागत करने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विजन से प्रेरित होकर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सक्रिय भागीदार के तौर पर विशेष अभियान चला रहा है

नवंबर 2024 से अगस्त 2025 के दौरान सांसदों से प्राप्त 493 संदर्भों, मंत्रिमंडल के 2 प्रस्तावों, राज्य सरकारों के 104 संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्यालय के 30 संदर्भों का निपटारा किया गया; 40880 जन शिकायतों और 1864 जन शिकायत अपीलों का भी निस्तारण हुआ

मंत्रालय ने क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर 2405 स्वच्छता अभियान आयोजित किए

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छता को संस्थागत करने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विजन से प्रेरित होकर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सक्रिय भागीदार के तौर पर विशेष अभियान चला रहा है।

गृह मंत्रालय और इसके संगठनों नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक मासिक आधार पर लंबित मामलों को कम करने के लिए सक्रिय रूप से विशेष अभियान चला रहे हैं।

इस अवधि की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- मंत्रालय ने क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर 2405 स्वच्छता अभियान आयोजित किए।
- सांसदों के 493 संदर्भों, मंत्रिमंडल के 2 प्रस्तावों, राज्य सरकारों के 104 संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्यालय के 30 संदर्भों का निपटारा किया गया।
- नवंबर 2024 से अगस्त 2025 के दौरान प्राप्त 40880 जन शिकायतों और 1864 जन शिकायत अपीलों का मंत्रालय द्वारा निपटारा किया गया।
- गृह मंत्रालय/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के कार्यालयों में 79774 वर्ग फुट स्थान खाली किया गया।

डेटा संकलन को सुचारू बनाने और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल का उपयोग कर रहा है, जिसमें मंत्रालय के सभी प्रभागों के साथ-साथ केन्द्रशासित प्रदेशों/दिल्ली पुलिस द्वारा अभियान से संबंधित डेटा अपलोड किया जाता है। इससे प्रभागों/कार्यालयों के साथ कुशलतापूर्वक समन्वय स्थापित करने में मदद मिली है, जिससे बिना किसी देरी के सही डेटा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा आयोजित विशेष अभियान 5.0 के लिए गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से विशेष अभियान संचालित कर रहा है, जिसमें टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थलों पर ध्यान देने के साथ-साथ सांसदों से प्राप्त लंबित संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों, लोक शिकायतों/अपीलों का निपटारा और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल है।

मंत्रालय में विशेष अभियान 5.0 की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस बलों (CPOs) द्वारा विशेष अभियान के महत्व पर जोर दिया गया है और वे निर्धारित मानकों के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हैं।

वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने

उच्च-स्तरीय समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केन्द्र सरकार ने 27 राज्यों को रऊम्क्र के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को ठऊम्क्र के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (ठऊम्क्र) से प्रदान की गई है, इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि (रऊम्क्र) में वर्ष की शुरूआत में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन होना चाहिए। कुल 707.97 करोड़ रुपये की राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

उच्च-स्तरीय समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 903.67 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी है। कुल 903.67 करोड़ रुपये की राशि में से 676.33 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में होंगे। कुल 903.67 करोड़ रुपये की राशि में से हरियाणा के लिए 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपये को मंज़ूरी दी गई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

यह अतिरिक्त सहायता केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि में पहले से जारी की गई राशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के अधीन रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केन्द्र सरकार ने 27 राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इसके अलावा, 21 राज्यों को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (रऊट्क्र) से 4,571.30 करोड़ रुपये और 09 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (ठऊट्क्र) से 372.09 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

क्रिकेट के बाद धोनी की नई उड़ान, बन गए प्रोफेशनल ड्रोन पायलट, खुद आकर की बड़ी घोषणा

(जीएनएस)।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और आइकन एम.एस. धोनी ने अब एक नया मुकाम हासिल किया है। क्रिकेट के मैदान पर अपनी कप्तानी और शांत स्वभाव के लिए मशहूर धोनी अब DGCA (Directorate General of Civil Aviation) द्वारा प्रमाणित ड्रोन पायलट बन गए हैं।

धोनी ने Garuda Aerospace Pvt. Ltd. के साथ मिलकर DGCA ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा किया है। यह कोर्स DGCA द्वारा अप्रूव्ड RPTO (रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन) के अंतर्गत कराया गया है। धोनी ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और बताया कि वह इस नए कौशल को सीखने के बाद बेहद उत्साहित हैं।

मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (एमएआईडीएस) में चार रोगियों पर स्वदेशी अनुकूलित टेम्पोरो- मैंडिबुलर जॉइंट (टीएमजे) का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मील का पत्थर

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और एमप्रगति- आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एमएआईडीएस में अनुकूलित टीएमजे प्रत्यारोपण का सफल प्रत्यारोपण भारत के मेडटेक क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दशार्ता है : श्री जे.पी. नड्डा

यह विकास दुनियाभर में स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने के लिए नैदानिक विशेषज्ञों, इंजीनियरों और शोधकताओं के बीच सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करता है : महानिदेशक आईसीएमआर

भारत के चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक प्रगति के रूप में, मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान (एमएआईडीएस), नई दिल्ली की नैदानिक टीम द्वारा चार रोगियों पर एक अनुकूलित टेम्पोरो- मैंडिबुलर जोड़ (टीएमजे) प्रत्यारोपण प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई।

एमएआईडीएस, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआर) के रूप में कार्य करता है। समन्वय विकास अनुसंधान प्रभाग के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण एवं निदान मिशन सचिवालय (एमडीएमएस) द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने के भारत के निरंतर प्रयासों के तहत यह उपलब्धि हासिल की है।

टीएमजे प्रत्यारोपण को आईसीएमआर- डीएचआर-मेडटेक उत्पाद विकास त्वरण गेटवे ऑफ इंडिया (एमप्रगति) में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था - जो आईआईटी दिल्ली में एमडीएमएस द्वारा समन्वित एक अत्याधुनिक सुविधा है। यह नवाचार आयातित प्रत्यारोपणों पर निर्भरता कम करने और भारतीय रोगियों के लिए किफायती, उच्च- गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों तक पहुँच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विकसित भारत के प्रमुख स्तंभों में से एक है। यह भारत के अनुसंधान सहयोग की मजबूती, शैक्षणिक संस्थानों और नैदानिक केंद्रों के बीच बढ़ते तालमेल और एक मजबूत स्वदेशी चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र के उद्भव का उदाहरण है।

इस उपलब्धि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री जे.पी. नड्डा ने कहा, "आईसीएमआर और एमप्रगति-आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एमएआईडीएस में अनुकूलित टीएमजे इम्प्लांट का सफल प्रत्यारोपण, भारत के मेडटेक क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दशार्ता है। यह उपलब्धि दशार्ती है कि कैसे मजबूत अनुसंधान और नीतिगत समर्थन से समर्थित घरेलू नवाचार, स्वास्थ्य सेवा में किफायती और प्रभावशाली प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।"

आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा, "यह प्रगति वास्तविक दुनिया के स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने के लिए नैदानिक विशेषज्ञों, इंजीनियरों और शोधकताओं के बीच सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करती है। आईसीएमआर को ऐसे नवाचारों का समर्थन करने पर गर्व है जो न केवल लागत कम करते हैं बल्कि रोगियों में परिणामों में भी सुधार करते हैं, जिससे किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों में भारत का नेतृत्व और मजबूत होता है।"